बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्षः 23 ○ अंकः 153 ○ नई दिल्ली ○ सोमवार 16 जून 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्यः 3 रूपया ○ पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

बन्ना हॉप कैच को एमसीसी ने माना अवैध, इंटरनेशनल क्रिकेट में कब से लागू होगा नियम?

नई दिल्ली। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने बन्नी हॉप यानी सीमा रेखा के बाहर कई बार हवा में उछ्कर कैच करने को अवैध माना है। इसे लेकर नए नियम इसी महीने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्लेइंग इलेवन और अगले साल अक्टूबर से एमसीसी के नियमों में शामिल कर लिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद बीबीएल 2023 के दौरान माइकल नेसर और 2020 में मैट रेनशॉ की मदद से टॉम बैंटन द्वारा लिए गए शानदार कैच वैध नहीं माने जाएंगे। आईसीसी ने इस लेकर अपने सदस्य बोर्ड को एक नोट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार कुछ बेहतरीन कैच देखने को मिले लेकिन इस नियम के कारण कुछ असामान्य देखने वाले कैच भी वैध माने गए.

दिल्ली के अस्पतालों में गर्मी से हाहाकार, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली ।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने रिकॉर्ड तोड़ भीष्ण गर्मी की के बीच अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर आरोप लगाया है कि गर्मी के कारण अस्पतालों में जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है वहीं दिल्ली सरकार बीमार लोगों को अस्पतालों में व्यवस्थित सुविधाएं देने तक में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. उनका कहना है कि हीट वेव से निपटने के लिए व्यापक योजना की घोषणा के बावजूद 45 डिग्री तापमान में जहां मरीज अपनी बीमारी से अधिक प्रभावित हो रहे है वहीं उनको अस्पताल तक लाने वाले सहायक लोगों को अस्पताल में बैठने तक की सुविधा नहीं है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं का बखान कर रही है. कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष का आरोप है कि अस्पतालों में मरीजों के तीमारदार खुले में बैठने को मजबूर है. इनके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में मराजों के इंजतार करने की जगह पंखे तक नहीं है और भीड़ के कारण साथी लोगों को अंदर बैठने तक नही दिया जा रहा. कहीं परिजन पेड़ के नीचे

बैठने को मजबूर है तो कहीं भीष्ण गर्मी में टीन शेड के नीचे खड़ा होने को मजबूर हैं, धूप से बचने के लिए टीन शेड की तपत में मजबूरी में खड़े है. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जो गर्मी से प्रभावित मामले आ रहे है वो रिक्शा चालक, मजदूर, सड़कों अजीविका चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग है जिनमें पेट दर्द, उल्टी, पानी की कमी और चक्कर आने आदि शिकायतें है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार है, पंखे तक नहीं है, मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कुछ अस्पतालों में वाटर कूलर लगे है लेकिन पानी नहीं है. लिफ्ट तक काम नही कर रही है, जिससे मरीजां और परिजनों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है.

बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है. दिवेंद्र यादव ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार कड़कड़डूमा स्थित हेडगेवर अरोग्य अस्पताल में ओपीडी में ओपीडी में 7-10 प्रतिशत मरीज भीषण गर्मी से जुड़ी बीमारियों के है, मरीजों की गंभीर हालात के बावजूद डाक्टर मरीजों को कह रहें है भर्ती करने की जरुरत नहीं है. ऐसी ही हालत जीटीबी अस्पताल, स्वामी दयानन्द अस्पताल की है जहां पर गर्मी में बुनियादी सुविधाओं के साथ अन्य व्यवस्था ओझल है. उन्होंने कहा कि यदि इन अस्पतालों की जगह अगर दिल्ली में 30-40 सरकारी अस्पतालों के हालातों का आकलन करें तो हालात अत्यधिक संवेदनशील हैं. देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने 100 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों को वेंटिलेटर से आईसीयू में पहुंचा दिया है. भीषण गर्मी के कारण मरीजों की बढ़ती भीड़ ने अस्पतालां में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की कमी की वास्तविकता को उजागर कर दिया है.

ट्रंप ने 13वीं बार भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम का दावा किया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल

नई दिल्ली । कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न मौकों पर 13 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इन दावों के बारे में कब बोलेंगे। कांग्रेस नेता और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति 13 बार दावा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जयराम रमेश ने विभिन्न रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताया कि कब-कब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की बात कही। उन्होंने लिखा कि जब भारत अहमदाबाद विमान हादसे के दुख से ग्रस्त है, ऐसे समय में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम कराने का दावा किया। इससे पहले कल भी केनेडी सेंटर में उन्होंने ऐसा कहा था। प्रधानमंत्री कब तक इस पर चुप्पी साधे रखेंगे। इससे पहले गुरुवार

को जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका के आर्मी डे पर आमंत्रित किया गया है। यह खबर भारत के लिए कूटनीतिक के साथ ही रणनीतिक रूप से भी बड़ा झटका है। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय कूटनीति को अमेरिका से तीन बड़े झटके लगे हैं। यह हमारी अमेरिकी नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह एक चेतावनी है। पहले अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ शानदार सहयोगी बताया। यह अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व की तरफ से अजीब बयान है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दूसरा बड़ा झटका असिम मुनीर को 14 जून को आयोजित हो रहे यूएस आर्मी डे के लिए आमंत्रित किया जाना है। ये वही आसिम मुनीर है, जिसने पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही भड़काऊ और विभाजनकारी बयान दिया था। तीसरा झटका अमेरिकी विदेश विभाग का ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने फिर से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम राष्ट्रपति ट्रंप ने कराया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसमें भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए।

पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया। 10 मई को दोनों पक्षों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच वार्ता के बाद संघर्ष विराम हो गया। ट्रम्प बार-बार दावा करते रहे हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई।

हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम हुआ और इसमें किसी भी तीसरे देश ने दखल नहीं दिया।

सवारी बैठाने के विवाद में दिल्ली में ई-रिक्शा चालक की पीटकर हत्या, एक आरोपी हिरासत में... पूछताछ

नई दिल्ली । द्वारका साउथ इलाके में सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में एक ई-रिक्शा चालक की पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र यादव (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस एक आरोपी हरिपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धर्मेंद्र यादव अपने माता-पिता, भाई जीतेंद्र यादव और बहन के साथ गोयला गांव में रहता था। वह ई-रिक्शा चलाता था, जबकि जीतेंद्र सिक्योरिटी गार्ड है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 10 जून की रात पुलिस को इंदिरा गांधी अस्पताल से सूचना मिली कि एक शख्स की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र यादव के रूप में हुई। अस्पताल में पुलिस को मृतक का भाई जीतेंद्र यादव मिला, जिसने बताया कि उसका भाई ई-रिक्शा चलाता था। 9 जून को सवारी बिठाने को लेकर उसके भाई का सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन के पास अन्य ई-रिक्शा चालकों से झगड़ा हो गया था। अन्य ई-रिक्शा चालकों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसका गला सूज गया था। घटना के बाद वह उसे लेने सेक्टर 18 द्वारका आया था, जहां से दोनों भाई घर चले गए। अगले दिन रात में धर्मेंद्र की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह उसे इंदिरा गांधी अस्पताल लेकर गया, लेकिन हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे डीडीयू अस्पताल ले जाने की सलाह दी। वहां से जाने के दौरान धर्मेंद्र बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की, जिसमें चश्मदीदों ने बताया कि धर्मेंद्र का ई-रिक्शा चालकों से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद पांच आरोपियों की पहचान की, जिसमें से पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी कुतुब विहार निवासी हरिपाल सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर छानबीन कर रही है।

दिल्ली में होगी नई आबकारी नीति, भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम, शराब बिक्री में लाई जाएगी पारदर्शिता

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के लिए एक नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है, जिसमें शराब की गुणवत्ता, बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस नीति की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक् इस बार आबकारी नीति केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई आबकारी नीति के तहत न केवल वैज्ञानिक गुणवत्ता परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग में पारदर्शिता लाई जाएगी, बल्कि जन जागरूकता अभियान चलाकर शराब के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण किया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक नई नीति तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य

सचिव धर्मेंद कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को दी गई है. यह समिति देश के कई राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर रही है, ताकि दिल्ली में प्रभावशाली और समाजोन्मुख मॉडल को अपनाया जा सके. समिति 30 जून तक नई नीति का प्रस्ताव तैयार करेगी और इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी, नई आबकारी नीति में समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता नहीं होगा,साथ ही यह नीति दिल्लीवासियों के विश्वास पर खरी उतरने वाली होगी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक पिछली सरकार की आबकारी नीति को आड़े हाथों लेते हुए उसे भ्रष्टाचार पूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया, साथ ही दावा किया की पिछली आप सरकार की नीति के जरिये कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ, बल्कि जनता का विश्वास भी टूटा और असफलता का परिणाम यह रहा कि नीति को वापस लेना पड़ा और कई शीर्ष नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी. ऐसे में अब बीजेपी सरकार में नई आबकारी नीति को केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व का माध्यम बताया गया है, जो दिल्ली के नागरिकों के हित में तैयार की जा रही है.

हीटवेव से झुलसी दिल्ली को बारिश से मिलेगी राहत! आईएमडी ने दिया अलर्ट

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, लेकिन लोगों को यह गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा की महसूस हो रही है. तापमान के फील्स लाइक फिचर में इसे देखा जा सकता है. गर्म हवाओं और हीटवेव के चलते जनजीवन प्रभावित है. लेकिन अब दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज को राजधानी में बारिश और आंधी की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं. दिल्लीवासियों के लिए यह गर्मी से राहत देने वाली स्थिति हो सकती है. गुरुवार (12 जून) को राजधानी में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां हीट इंडेक्स 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. साथ ही, कुछ इलाकों में तेज हवाएं और तूफान जैसी स्थिति बन सकती है. किसानों और आम लोगों को इस दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. इन बदलावों से न केवल गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार की संभावना है. हालांकि राहत की यह उम्मीद पूरी तरह से मानसून पर भी निर्भर करेगी. इस बार मानसून दक्षिण भारत में लगभग समय पर पहुंच गया है, लेकिन उत्तरी भारत में इसकी आमद थोड़ी देरी से हो रही है. इसी कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को लंबे समय तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो यह गर्मी के थपेड़ों से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संस्थागत मध्यस्थता पर दिया जोर, कहा- यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संस्थागत मध्यस्थता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दिल्ली में एक सम्मेलन में मंत्री ने यह भी कहा कि संगठनों को समय की आवश्यकता के अनुसार लचीला और कठोर बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ताकि उनके हित सुरक्षित रहें और वे राष्ट निर्माण में योगदान दे सकें। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अधिकारियों को जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने संगठन के वित्तीय हितों के लिए प्रचलित रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने अफसोस जताया कि मध्यस्थता भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं यह अवधारणा विफल हो गई है और अन्य देश अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के केंद्र बन गए। उन्होंने आशा जताई कि भारत शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का नया केंद्र बनकर उभरेगा। सम्मेलन में ओएनजीसी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने कहा कि समय ही धन है, इसलिए मध्यस्थता की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की जरूरत है। वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना व्यापार तंत्र के लिए आवश्यक है। साथ ही मध्यस्थता को अधिक कॉर्पोरेट और कम कानूनी बनाना चाहिए। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विवाद के मुख्य तीन कारण होते हैं। पहला अधिकारियों का अत्यधिक रूढ़िवादी होना, जो अपनी जान बचाने के लिए जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। दूसरा विक्रेताओं का अत्यधिक आशावादी होना, जो कम बोली पर ठेके ले लेते हैं और बाद में काम पूरा करने में विफल हो जाते हैं और स्थिति से बचने के लिए विवाद पैदा करते हैं। जबकि तीसरा अनुबंधों में कठोरता, जो कार्य को पूरा करना कठिन बना देती है। विधि सचिव अंजू राठी राणा ने कहा कि सरकार मध्यस्थता और मध्यस्थता प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विधि मामलों के विभाग के निर्देश का उल्लेख किया, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने, मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हेमंत गुप्ता ने कहा कि वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए तदर्थ प्रणाली के बजाय संस्थागत मध्यस्थता को अपनाने के लिए पक्षों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। लोगों को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थता की तुलना में संस्थागत मध्यस्थता के लाभों को समझने के लिए इसे चुनना होगा।

प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे, रेखा सरकार पर भड़के मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों की बात करते हुए एक बार फिर रेखा सरकार को घेरा है। सिसोदिया का कहना है कि भाजपा सरकार मे प्राइवेट स्कूल माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। आप नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला है। दरअसल, एक्स पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रशांत विहार के एक स्कूल में बच्चों को छुट्टी के बाद जबरन रोके रखा गया क्योंकि वे स्कूल वैन से नहीं आते। जिसके बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, दिल्ली में छोटे-छोटे मासूम बच्चों को छुट्टी के बाद स्कूल में रोककर रखने की सजा दी गई। इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता स्कूल वैन के नाम पर प्राइवेट स्कूल की से लूट बचाना चाहते हैं और खुद उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। आप नेता ने रेखा सरकार को घेरते हुए आगे लिखा, भाजपा सरकार में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। बच्चों को डराकर, अभिभावकों को धमकाकर भाजपा कौन सी क्रांति लाना चाहती है? शर्म लिहाज या मानवता नाम को कोई चीज है दिल्ली की इस भाजपा सरकार में।

एअर इंडिया विमान के यात्री से वसूली के आरोप पर गृह मंत्रालय का जवाब, कहा- वीजा खत्म होने का शुल्क लिया

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) अहमदाबाद से हादसे का शिकार हुए एअर इंडिया विमान के यात्री से वसूली किए जाने के आरोपों पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यात्री का वीजा खत्म हो गया था। इसलिए शुल्क वसूला गया। हादसे में मृत यात्री के रिश्तेदार ने अहमदाबाद आव्रजन अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि एअर इंडिया विमान दुर्घटना में मृत यात्री के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया था कि यात्री के परिवार से विमान में चढ़ने के लिए इमिग्रेशन अधिकारी को 1000 पाउंड जुर्माना वसूल किया गया। इस मामले की जांच के बाद सामने आया कि यात्री मास्टर रुद्र किशन मोधा ने समय पर वीजा शुल्क और जुर्माना नहीं जमा किया था। इसके लिए उनसे कुल राशि लगभग 91,150 रुपये लिए गए। यात्रियों को निकास परमिट देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि यात्री मास्टर रुद्र किशन मोधा ब्रिटिश पासपोर्ट धारक थे। उनकी जन्मतिथि 22 अगस्त 2023 थी। जबकि यूके पासपोर्ट जारी होने की तिथि 10 अप्रैल 2024 थी। इस हिसाब से यात्री रुद्र भारत में अधिक समय यानि एक साल दो महीने और दो दिन रहे। एक वर्ष से अधिक समय के लिए यूके पासपोर्ट वीजा शुल्क 484 डॉलर है। भारतीय रुपयों में यह 484*85 यानि 41,140 रुपये होता है। जबकि 90 दिनों से अधिक के लिए जुर्माना 50,000 रुपये तय है। इसलिए वीजा शुल्क 41,140 रुपये और जुर्माना 50,000 रुपये जोड़कर कुल 91,140 रुपये लिए गए थे। इसके बाद बच्चे का निकास परमिट जारी किया गया था।

झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर बहजेपी सरकार बनने का प्रसाद दिया जा रहा, सौरभ भारद्वाज का हमला

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जनता से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी वर्ग की अनदेखी नहीं की जाएगी और सभी को बीजेपी सरकार बनने का प्रसाद दिया जाएगा. अब हम सभी ने देखा की सरकार में आते ही बीजेपी ने पूरी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का प्रसाद मिडिल क्लास वर्ग को दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर वहां रहने वाले लोगों को बीजेपी सरकार बनने का प्रसाद दिया जा रहा है, और अब गर्मियां शुरू होते ही पीपीएसी चार्ज बढाकर रेखा गुप्ता की सरकार ने एक और प्रसाद पूरी दिल्ली की जनता को दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुलाई 2024 का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का एक वीडियो पत्रकारों को दिखाया गया. इसके संबंध में जानकारी देते हुए सौरभ भारद्वाज ने बताया, साल 2024 में जब पीपीएसी चार्ज 8त्न बढ़ा था, तो वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के कई सांसद और कई अन्य नेता जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उस समय दिल्ली में रही आम आदमी पार्टी की सरकार को चोर बताया था. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि यह सीधे-सीधे दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिली भगत है और एक बड़ा भ्रष्टाचार है. सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10.5फीसदी पीपीएसी चार्ज बढ़ाया गया है. मैं वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछना चाहता हूं, कि आज जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उसे डाकू कहेंगे या महाचोर कहेंगे? मीडिया के माध्यम से वीरेंद्र सचदेवा जी से एक अन्य प्रश्न पूछते हुए भारद्वाज ने कहा, विपक्ष में रहते हुए वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा था कि बिजली कंपनियों के रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन देने के नाम पर जो बिजली बिल में चार्ज लगाए जाते हैं, वह गलत हैं. बिजली कंपनियों के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन का भुगतान उपभोक्ता नहीं करेगा. आप नेता ने कहा कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बने हुए लगभग 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली के बिलों से बिजली कंपनी के कर्मचारी की पेंशन के नाम पर लगने वाले चार्ज को हटाया नहीं गया है, वीरेंद्र सचदेवा जी बताएं कि भाजपा की दिल्ली सरकार इन चार्ज को कब हटा रही है? दिल्ली के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में बीजेपी की नवनिर्वाचित सरकार ने न सिर्फ बिजली के दामों को बढ़ाया है बल्कि जगह-जगह पर बिजली के लंबे-लंबे कट लग रहे हैं. इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती है. एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, छतरपुर इलाके में रात को 8:00 बजे बिजली गई और अगले दिन सुबह 10:00 बजे बिजली आई, लगभग 14 घंटे का बिजली का कट छतरपुर इलाके में लगाया गया.

क्षेत्र के परेशान लोगों ने रास्ता जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि यह केवल छतरपुर इलाके की बात नहीं है, लगभग दिल्ली के सभी पॉश इलाकों का यही हाल है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ की बिजली के लंबे-लंबे कट लगे हो. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में लोगों ने अपने घरों से इनवर्टरों को हटा दिया था, लोग इनवर्टर को भूल गए थे। लेकिन जब से दिल्ली में क्ष्छ्क्षकी सरकार बनी है, लोगों ने दोबारा से अपने घरों में इनवर्टर लगाना शुरू कर दिया है.

एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग सर्वे संतु निरामया यानें सभी रोग मुक्त हों

भारत की अत्यंत प्राचीन विरासत में से एक योग भी है,आदि अनादि काल से ही योग एक जीवन जीने की कला और आज के आधुनिक डिजिटल युग में एक विज्ञान और औषधी रहित चिकित्सा पद्धति के रूप में वैश्विक स्तरपर लोकप्रिय हो चुका है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है,योग दिवस पर भारत का रिकॉर्ड-संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून को 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 जून 2025 को राष्ट्रीय कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा,जहां पीएम 5 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही, देश भर में एक लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो इसे इतिहास में सबसे बड़े समन्वित योग प्रदर्शनों में से एक बनाएगा। उन्होंने योग आंध्र अभियान - जो राज्य भर में 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का समुदाय तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है।चूँकि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग सर्वे संतु निरामया यानें सभी रोग मुक्त हों तथा 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है, विशाखापट्टनम में 5 लाख प्रतिभागियों के साथ पीएम बड़ा कॉमन योग प्रोटोकॉल का नेतृत्व करेंगे इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,पूरे भारत में एक लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम सत्र आयोजन की तैयारीयाँ,जो इसे इतिहास में सबसे बड़े समन्वित योग प्रदर्शनों में से एक बना सकता है। साथियों बात अगर हम 21 जून 2025 को होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की ऐतिहासिक तैयारीयों की करें तो, वैश्विक भागीदारी पर अद्यतन जानकारी साझा करते हुए आयुष मंत्रालय के सचिव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए 60 से अधिक देशों ने पहले ही संबंधित कार्यकलाप आरंभ कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भर में योग के प्रति उत्साही लोग सक्रिय रूप से एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम और दस प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं,जो इस आंदोलन के वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाते हैं।आयुष मंत्रालय के अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में आईडीवाई 2025 के परिमाण, विज़न और कार्यनीति का विवरण देते हुए एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने आईडीवाई आंदोलन की एक दशक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया,10 प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी और व्यापक तथा समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोगा त्मक साझेदारी पर प्रकाश डाला। साथियों बात अगर हम 100 दिनों से चल रही योग श्रृंखला की करें तो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में 100 दिनों तक चलने वाले दस सिग्नेचर इवेंट यानी प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिन्हें समाज के [illegible]

जीवन के समग्र तरीके के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। - समावेशिता के लिए योग समावेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए योग बंधन तक -ये कार्यक्रम योग को मैट(चटाई) से लेकर आम जनता तक ले जाने के सरकार के रणनीतिक विज़न को दर्शाती हैं। दिल्ली, भुवनेश्वर, [illegible] दिवसीय, 50 दिवसीय और 25 दिवसीय आयोजनों की श्रृंखला के प्रति जनता की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया ने मुख्य कार्यक्रम की ओर अग्रसर होने में अहम योगदान दिया है।योग केवल आसन करने और सांस लेने का अभ्यास भर नहीं है - यह जीवन जीने का एक तरीका है, मीडिया के सहयोग से लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस [illegible] जो लाखों लोगों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करे और एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में सहायता करे। साथियों बात अगर हमयोगदिवस 2025 को एतिहासिक बनाने की करें तो, अधिकारी ने कहा वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्वभर में असाधारण उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नई दिल्ली में पहले रिकॉर्ड आयोजन से लेकर मैसूर, न्यूयॉर्क और श्रीनगर में ऐतिहासिक समारोहों तक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रत्येक आयोजन ने स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति की साझा खोज में विविध संस्कृतियों के लोगों को एकजुट किया है। उन्होंने इस वर्ष की उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, जब हम 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 केवल एक स्मरणोत्सव भर नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रयासों को बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों तक योग की पहुंच को बढ़ाने का एक सामूहिक आह्वान है। उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी,एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रस्तुत वैश्विक स्वास्थ्य विज़न के अनुरूप है और सर्वे सन्तु निरामया के भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को दर्शाता है, जिसका अर्थ है - सभी रोग मुक्त हों। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आईडीवाई 2025 के भव्य समारोह की औपचारिक शुरुआत है और 21 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पीएम की अगुवाई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है।

सम्पादकीय...

भयानक हादसा

12 जून, 2025 का दिन भारत के इतिहास में काला गुरुवार के रूप में याद किया जाएगा। दोपहर एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना की खबर आते ही भयावह मंजर दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक आने लगे थे। हादसे की जो तस्वीरें वायरल हुईं वो इतनी भयानक थीं जिसे देखकर इंसान की रूह भी कांप जाए। तभी देशवासियों को इस बात का अहसास हो चुका था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। शाम तक जो दिखाई दिया वो बहुत भयानक था। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं। केवल नरकंकाल ही बचे थे कि पहचान करना भी मुश्किल था। इसे कुदरत का क्रूर प्रहार कहा जाए, मानवीय चूक या फिर तकनीकी गड़बड़ी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो चेहरे चंद मिनट पहले विमान में मुस्कुराते हुए चढ़े थे वे अब मलबे में तबदील हो चुके थे। विमान आग का गोला बनकर मेडिकल कॉलेज के होस्टल पर गिरा, तो काले धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रतिभाशाली और बिजनेस टाइकून और हादसे की चपेट में आए मेडिकल छात्रों समेत 265 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई यात्रियों समेत इतने लोगों का मारा जाना स्तब्ध कर देने वाला है। हर पीड़ित परिवार की अपनी-अपनी दुःख भरी दास्तान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल का दौरा किया। हादसे से हर कोई स्तब्ध है। दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने विमान यात्रा की सुरक्षा को लेकर गम्भीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रीमलाइनर 787 को अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है। इसकी क्षमता एक ही बार में 14 घंटे उड़ान भरने की है। ड्रीमलाइनर डेथलाइनर कैसे बना इसको लेकर पहले ही चिंताएं चल रही थीं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा पर सवाल हाल के वर्षों में कई बार उठ चुके हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग के इंजीनियर सैम सालेहपुर ने खुलासा किया कि 787 के फ्यूजलेज को जोड़ने की प्रक्रिया में खामियां हैं, जिसके कारण विमान का ढांचा समय से पहले कमजोर हो सकता है। सालेहपुर ने दावा किया कि प्रोडक्शन में शॉर्टकट्स किए गए, जिससे विमान के जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कुछ समय बाद में बड़े संकट का कारण बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बोइंग ने उनकी चिंता को नजरअंदाज किया और उन्हें 787 प्रोजेक्ट से हटाकर 777 प्रोजेक्ट में भेज दिया। इसके बाद, अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ने सालेहपुर के दावों की जांच शुरू की। मई 2024 में एफएए ने पाया कि बोइंग के दक्षिण कैरोलिना प्लांट में कर्मचारियों ने विंग-टू-फ्यूजलेज जोड़ों की जांच को छोड़ दिया था और रिकॉर्ड में इसे पूरा दिखाया। इस ÷गलत बर्ताव÷ को बोइंग ने स्वीकार भी किया लेकिन दावा किया कि यह तत्काल उड़ान सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। एफएए ने बोइंग को बाकी बचे सभी 787 विमानों की दोबारा जांच करने और पहले से सेवा में मौजूद विमानों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इतिहास विवादों से भरा रहा है। 2013 में बैटरी की समस्याओं, फ्यूल रिसाव और ब्रेक से संबंधित तकनीकी खामियों के कारण कई देशों ने इस विमान को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया था। 2021 में एफएए ने उत्पादन में खामियों की वजह से 787 की डिलीवरी को 2022 तक रोक दिया था। हाल ही में, मार्च 2024 में लैटम एयरलाइंस के एक 787 विमान में अचानक गोता लगाने की घटना ने 50 से अधिक यात्रियों को घायल कर दिया, जिसके कारण एफएए ने पायलट सीटों की जांच के लिए आदेश जारी किए। बोइंग के अन्य विमान भी सुरक्षा को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। वर्ष 2018 में लॉयन एयर फ्लाइट 610 और 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के हादसे, जिनमें कुल 346 लोगों की जान गई थी, के बाद से बोइंग की निर्माण प्रक्रिया कठघरे में रही है। जनवरी, 2024 में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बोइंग 737 विमान का आपातकालीन दरवाजा ही उड़ गया था, जिसके बाद विमानों को ग्राउंड कर दिया गया था। बोइंग कम्पनी करीब तीन दर्जन ऑडिट में विफल रही है और अमेरिकी न्याय विभाग ने आपराधिक जांच शुरू की थी। हैरानी की बात यह है कि ड्रीमलाइनर में खामियों को उजागर करने वाले सैम सालेहपुर ने रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली थी। ऐसा भी नहीं है कि विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल और सह पायलट क्लाइव कुंदर अनुभवी नहीं थे। उड़ान भरते ही कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल की थी। मेडे कॉल तब कहा जाता है जब कोई विमान पूरी तरह खतरे में होता है। यह कॉल अत्यंत तनाव या खतरे में की जाती है। भारत में पहले भी कई विमान हादसे हो चुके हैं लेकिन विमान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिएं उनको लेकर संदेह उत्पन्न होता है। एयर इंडिया को लेकर पहले ही यात्रियों को कई तरह की शिकायतें रही हैं। यह भी कहा जाता है कि एयर इंडिया के विमान काफी पुराने हो चुके हैं, जिनमें तकनीकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। टाटा ने 27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, तब से अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। कभी विमानों का हाइड्रोलिक सिस्टम ठप्प हो जाता है, कभी यात्री एयर कंडीशन बंद रहने की शिकायतें करते हैं। अनेक विशेषज्ञ पुराने विमानों को हटाने की सलाह देते हैं। विमान दुर्घटना किन कारणों से हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसका पता तो जांच से चलेगा लेकिन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और एयर इंडिया को गम्भीरता से जांच कर जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के लिए बोइंग कम्पनी को भी कठघरे में खड़ा करना होगा। विमान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अगर सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया तो यात्रियों का भरोसा ही उठ जाएगा।

रूपाणी के लिये अनलकी साबित हुआ 'लकी नंबर'

ऐसा लगता है कि गुजरात के दिवंगत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का लकी नंबर आखिरकार उनके लिए अशुभ साबित हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में रूपाणी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की तारीख 12/06 है। यह वही नंबर है जो उनकी कार की नंबर प्लेट पर हमेशा होता था। वह इस संयोजन को अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। गुजरात के लोगों को याद है कि उनकी पहली से लेकर अब तक की सभी कारों में यही संयोजन था। यह नंबर निश्चित रूप से उनके लिए भाग्यशाली थे। वह एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था। दिलचस्प यह है कि उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण एयर इंडिया विमान में पंक्ति संख्या 12 में बैठने पर जोर दिया। दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वासकुमार ठीक सामने वाली पंक्ति में बैठे थे। विमान में आग लगने से कुछ सैकेंड पहले वह अपने बगल के आपातकालीन निकास द्वार से निकल पाने में सफल रहे। रूपाणी इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह मारे गए और तारीख वही थी, जिसे वह हमेशा भाग्यशाली मानते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय युद्ध के कई उतार-चढ़ावों के बीच अमेरिकी सेना की ओर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को एक आश्चर्यजनक निमंत्रण है। वाशिंगटन से मिली रिपोर्टों के अनुसार, मुनीर को 14 जून को अपनी 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिकी सैन्य परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह निमंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेंटागन और पाकिस्तान सेना के बीच पारंपरिक संबंधों के पुनरुद्धार का प्रतीक है। दशकों के घनिष्ठ संबंधों के बाद, 2020 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने के बाद दोनों सेनाओं के बीच संबंध ठंडे पड़ गए थे। पाकिस्तानी सेना के चीन के साथ संबंध, जो पहले से ही काफी मजबूत थे, और भी करीबी हो गए हैं। शायद पाकिस्तान और चीन के बीच बहुत ही स्पष्ट निकटता ने अमेरिका को चिंतित कर दिया है जो अब पाकिस्तानी सेना के साथ पुराने संबंध फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मुनीर को वर्षगांठ परेड में शामिल होने का निमंत्रण इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान को निमंत्रण नहीं मिला है। हाल के हफ्तों में भाजपा के मध्य प्रदेश के नेताओं ने पार्टी को इतना शर्मिंदा किया है कि पार्टी सार्वजनिक रूप से बोलते समय संयम और परिपक्वता की कला सीखने के लिए पूरी राज्य इकाई के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। संकट की गंभीरता ने शीर्ष नेताओं को इतना चिंतित कर दिया है कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से कुछ सत्रों की निगरानी करेंगे। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के नेताओं को यह सिखाना है कि मीडिया से बात करते समय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते समय क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। हाल के हफ्तों में मध्य प्रदेश के नेताओं की मुंहफट बातें करने की प्रवृत्ति चरम पर पहुंच गई है, जब कम से कम तीन शीर्ष नेताओं ने एक के बाद एक पार्टी को शर्मिंदा किया है। पहले राज्य मंत्री विजय शाह थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को संबोधित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को मैदान में उतारने के बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। उनकी अप्रिय टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जिसने उनसे माफी मांगने को कहा और जांच का आदेश दिया। इसके बाद एमपी के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आए, जिनकी भारतीय सेना पर की गई टिप्पणियों को अपमानजनक माना गया। और फिर कैलाश विजयवर्गीय थे, जो मध्यप्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। उन्होंने उन महिलाओं के बारे में अनाप-शनाप बातें कीं, जो ÷छोटे कपड़े÷ पहनती हैं, जिससे महिलाओं और विपक्षी नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। और भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। सरकार ने इसकी गंभीरता को पहचान कर इन्हें नसीहत दी है और अब इनको सुधारने की तैयारी शुरू की है। क्या लालू यादव के अलग हुए बेटे तेजप्रताप सुलह की कोशिश कर रहे हैं हाल ही में अपने पिता के 78वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, तेजप्रताप ने एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट अपलोड की। इसमें उन्हें अपने पिता की एक विशाल चित्रित तस्वीर के सामने दिखाया गया। तस्वीर के नीचे दो लाइनें थीं रात जितनी अंधेरी होगी, सुबह उतनी ही करीब होगी। बिहार में कई लोग इसे पिता से सुलह की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। याद दिला दें कि हाल ही में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे से नाता तोड़ लिया था, जब उसने फेसबुक पर एक पोस्ट में खुलासा किया था कि शादीशुदा होने के बावजूद वह किसी दूसरी महिला के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में था। इस पोस्ट ने बवाल मचा दिया था।

जाति जनगणना तय करेगी भावी राजनीति

नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है। घोषित कार्यक्रम से स्पष्ट है कि प्रक्रिया लम्बी चलेगी और भावी राजनीति पर दूरगामी असर डालेगी। भारत सरकार की घोषणा के मुताबिक अप्रैल से सितम्बर, 2026 तक घरों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद लोगों की गिनती होगी। दरअसल जाति जनगणना दो चरणों में होगी। एक अक्तूबर, 2026 से पहले चरण में पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर,लद्दाख,हिमाचल और उत्तराखंड) में जनगणना होगी। दूसरे चरण में एक मार्च, 2027 से शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना होगी। जाहिर है, भारत जैसे विशाल देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम आंकड़े आने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं, अगले साल होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी तथा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,पंजाब, मणिपुर, गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव भी जाति जनगणना के शोर और उसके श्रेय के दावों-प्रतिदावों के बीच ही निपट जाएंगे। बेशक इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। हमारे राजनीतिक दल तो वैसे भी हर मुद्दे को चुनाव में भुनाने में माहिर हैं। नियमानुसार यह जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना के बीच ही सावधानियों के साथ कई राज्यों में चुनाव तो कराए गए लेकिन जनगणना नहीं। 5 साल विलंब से लंबित जनगणना में अब जातियों की गणना भी की जाएगी।

हमारे देश में जाति जनगणना भले ही आजादी के बाद पहली बार हो रही हो, पर उस पर राजनीति पुरानी है। कांग्रेस और भाजपा, दोनों की छवि अतीत में जाति जनगणना विरोधी की रही है लेकिन अब वे ही उसका श्रेय लेना चाहती हैं। सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना को देश और समाज की विकास योजनाओं के लिए उपयोगिता से जोड़ कर पेश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह तो पहला कदम है, हमें आगे जा कर पता करना है कि उच्च पदों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव में भी श्रेय की होड़ शुरू हो गई है। समझ पाना मुश्किल नहीं कि सारा खेल सत्ता-राजनीति का है। जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय होते हुए भी बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों ने जाति सर्वे का दांव चला। इसीलिए जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले में भी राजनीतिक दबाव की भूमिका मानी जा रही है। कांग्रेस नीत यू.पी.ए. शासनकाल में 2011 की जनगणना में सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जाति के आंकड़े तो जुटाए गए लेकिन जारी नहीं किए गए। अगली जनगणना 2021 में होनी थी जो कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाई। जनगणना के इंतजार में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी रुका हुआ है।

आखिरकार इजरायल द्वारा ईरान पर रणनीतिक हमला किए जाने के वैश्विक मायनों को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे ।

जानकारों की मानें तो पहाड़ों में भी ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिसे अमेरिकी मदद के बिना इजरायल खत्म नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि इजरायल सिर्फ ईरानी परमाणु ठिकाने को ही नहीं, बल्कि उसकी खुमैनी सरकार को भी हटाना चाहता है। इसलिए इतना खतरनाक हालात पैदा किए हुए है। जाहिर है कि बिना अमेरिका, यूरोप व एशिया के नाटो देशों के इशारे के वह ऐसी हिमाकत कदापि नहीं कर सकता है। वहीं, हमले के बाद आईडीएफ ने कहा कि ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। इससे साफ है कि देर सबेर वह दूसरे मुस्लिम सरगना देश तुर्किये और तीसरे इस्लामिक आतंकवादी सरगना देश पाकिस्तान के ऊपर भी हमला अवश्य करेगा। फिलवक्त चूंकि पाकिस्तान व तुर्किये अमेरिका के सरपरस्त देश हैं, इसलिए इनकी बारी कब आएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ वक्त का इंतजार करना ही श्रेयस्कर होगा।

लीजिए एक और युद्ध का आगाज हो गया। इससे हथियार निर्माता कंपनियों की बाछें पुनः खिल गईं। कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता आखिरकार बत्तीस दांतों के बीच घिरी जिह्वा की तरह मुस्लिम देशों से घिरे एकमात्र यहूदी मुल्क इजरायल ने अपने रणनीतिक हिफाजत के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के सरगना देश ईरान पर निर्णायक हमला बोल दिया है, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रमों को ब्रेक लगाकर संभावित परमाणु हमलों से इजरायल के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समझा जाता है कि ईरान की बार-बार की बन्दरघुड़की का इजरायल ने करारा जवाब दिया है। इस्राइल ने ईरान के %परमाणु कार्यक्रम ठिकानों% पर अचानक हमला करके न केवल सबको चौंका दिया है बल्कि इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से अनिश्चितता के जद्दोजहद में धकेल दिया है। इससे महंगाई और बर्बादी दोनों बढ़ेंगी। वहीं, गुटीय युद्ध से बचने के लिए अमेरिका ने तत्काल यह साफ किया है कि इस कार्रवाई में वह शामिल नहीं है। वहीं, अब यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि रूस और चीन की रजामंदी के बाद ईरान भी पुरजोर जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे तीसरा विश्वयुद्ध भी भड़क सकता है। दरअसल, इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है, जो बताता है कि यह अपने आप में महज एक कार्रवाई नहीं बल्कि नया सिलसिला हो सकता है। हमलों का व्यापक रूप भी इसकी गंभीरता को स्पष्ट कर देता है। यह हमला भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई जैसा है, लेकिन अपने दृढ़ संदेश में ऑपरेशन राइजिंग लायन एक मजबूत संदेश देता है, जिससे इस्लामिक देशों की चूलें हिल चुकी हैं। वहीं, ईरान ने भी यह माना है कि इन हमलों में उसके कम से कम छह परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। यही नहीं, ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स के चीफ हुसैन सलामी के भी मारे जाने की खबर है। इससे ईरान ने जवाबी कार्रवाई का इरादा भी जता दिया है। वहीं, इस्राइली कार्रवाई के वैश्विक दुष्प्रभावों का संकेत इसी एक तथ्य से मिल जाता है कि पहले हमले के कुछ घंटों के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 13त्न बढ़ गई। जबकि कुछ शेयर बाजार रॉकेट की तरह भागे, और कुछ धराशायी हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्राइल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से हर हाल में रोका जाए और जरूरी हो तो उसके लिए बल प्रयोग से भी हिचका न जाए। क्योंकि उसका यह कहना है कि ईरान इस स्थिति में आ गया था कि कुछ दिनों के अंदर ही वह 15 परमाणु बम बना सकता था। जो इजरायल के खिलाफ ही उपयोग होता। ऐसे में उसने निर्णायक हमले किए। यह बात दीगर है कि इस्राइल के इन आरोपों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यह बात भी सत्य है कि इस मसले पर अमेरिका से ईरान की बातचीत चल रही थी। 15 जून रविवार को भी दोनों पक्षों में अगले दौर की वार्ता होनी थी। ऐसे में इस्राइल की अचानक की गई इस कार्रवाई के बाद सभी पक्षों की नजरें इस पर टिक गई हैं कि आगे घटनाक्रम कैसा रूप लेता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई का स्वरूप कैसा और उसका दायरा कितना बड़ा होता है। क्या वह खुद को इस्राइल के खिलाफ सांकेतिक कार्रवाई तक सीमित रखता है या फिर अमेरिकी दूतावासों व अन्य ठिकानों को भी अपनी जद में लेता है या होरमुज की खाड़ी से गुजरते जहाजों को भी निशाना बनाता है जहां से 21त्न ग्लोबल तेल की सप्लाई होती है। गौरतलब है कि इजरायली हमले के बाद वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा, परमाणु विज्ञानियों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया। उन्होंने ईरान पर हमले के बाद यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हुए इजरायली हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने तेहरान को अमेरिकी हितों और कर्मियों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। जबकि इजरायली रक्षा अधिकारी ने दावा किया कि हमलों में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी और उनके कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने एक आपात बैठक बुलाई। डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे की एहतियाती रणनीति तय की गई। चूंकि तेहरान में हुए धमाकों के बाद इराक और ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इससे वैश्विक वायुयान सेवाओं पर भी असर पड़ना लाजिमी है। वहीं, इजरायल ने ईरान में हमले के बाद देशभर में इमरजेंसी लागू की। इसके अलावा इस्राइल ने दुनिया भर में अपने दूतावास बंद करने का एलान किया है। साथ ही इस्राइल ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों पर यहूदी या इस्राइली प्रतीक न दिखाने की अपील की है। मालूम हो कि विगत कई दशकों से गाजा पट्टी में इजरायल के खिलाफ संघर्षरत फिलिस्तीनियों और हमास के आतंकियों को जहां ईरान, सीरिया, जॉर्डन आदि मुस्लिम देश खुला समर्थन दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान-तुर्किये-अजरबैजान जैसे कुख्यात मुस्लिम देश भी उन आतंकियों को गुप्त शह प्रदान कर रहे हैं। लिहाजा इजरायल ने अब तय कर लिया है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल मुस्लिम देशों को अब बारी-बारी से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद इसलिए इजरायल ने अब ऐसे मुल्कों की जड़ों पर ही हमला बोलने का निश्चय किया है, जिसकी खौफनाक शुरुआत भी कर दी है। जिसके बाद पश्चिम एशिया के दो कट्टर विरोधियों के बीच एक व्यापक युद्ध की आशंका तेज हो गई है। इसे 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जानकारों की मानें तो पहाड़ों में भी ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिसे अमेरिकी मदद के बिना इजरायल खत्म नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि इजरायल सिर्फ ईरानी परमाणु ठिकाने को ही नहीं, बल्कि उसकी खुमैनी सरकार को भी हटाना चाहता है। इसलिए इतना खतरनाक हालात पैदा किए हुए है। जाहिर है कि बिना अमेरिका, यूरोप व एशिया के नाटो देशों के इशारे के वह ऐसी हिमाकत कदापि नहीं कर सकता है। वहीं, हमले के बाद आईडीएफ ने कहा कि ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। इससे साफ है कि देर सबेर वह दूसरे मुस्लिम सरगना देश तुर्किये और तीसरे इस्लामिक आतंकवादी सरगना देश पाकिस्तान के ऊपर भी हमला अवश्य करेगा। फिलवक्त चूंकि पाकिस्तान व तुर्किये अमेरिका के सरपरस्त देश हैं, इसलिए इनकी बारी कब आएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ वक्त का इंतजार करना ही श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इजरायल-ईरान विवाद से जुड़े इस पूरे मसले पर वर्ल्ड इस्लामिक काउंसिल (ओआईसी) के लगभग 56 मुस्लिम सदस्य देश भी आपस में विभाजित हैं, क्योंकि जो अमेरिका के सरपरस्त हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं जो रूस-चीन-उत्तर कोरिया के समर्थक हैं, वो ईरान के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। चूंकि अमेरिका ने बड़ी सफाई से खुद को अलग कर लिया है, इसलिए अब यह रूस-चीन के ऊपर है कि वो खुलकर मैदान में आएंगे या नहीं। जबकि गुटनिरपेक्ष देश भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह इजरायल-ईरान युद्ध में भी अपनी तटस्थता बरकरार रखी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई : उड्डयन मंत्रालय

नई दिल्ली ।

गुजरात में 12 जून को 242 यात्रियों और चालक दल को लेकर लंदन जाने वाला विमान एआई 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। देखते ही देखते एअर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया था। हादसे में विमान में सवार 52 ब्रिटिश नागरिकों सहित 241 लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति हादसे में बच गया था, जिसका इलाज चल रहा है। मामले में सरकार ने शनिवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हादसे की पूरी कहानी बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने मीडिया को विस्तार से मामले की पूरी जानकारी दी। समीर कुमार सिन्हा ने बताया, 12 जून को दोपहर करीब दो बजे हमें सूचना मिली कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमने तुरंत एटीसी अहमदाबाद के जरिए इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। यह एआईसी 171 था और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, दो पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 बजे उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर यह ऊंचाई खोने लगा यानी इसकी ऊंचाई कम होने लगी। उन्होंने आगे बताया कि दोपहर 1:39 बजे पायलट ने अहमदाबाद एटीसी को मे डे की सूचना दी यानी पूरी तरह से इमरजेंसी थी। एटीसी के मुताबिक जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक एक मिनट बाद यह विमान मेघानीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एयरपोर्ट से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर थे। जहां तक विमान की बात है तो

- **अहमदाबाद विमान हादसा- मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंचा**
- **मलबे से एक और शव मिला**
- **एविएशन मिनिस्टर बोले- 3 महीने में मिलेगी जांच रिपोर्ट**

इस दुर्घटना से पहले विमान ने पेरिस-दिल्ली-अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी परेशानी के पूरी की थी। दुर्घटना के कारण दोपहर 2:30 बजे रनवे को बंद कर दिया गया और सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद शाम पांच बजे से अहमदाबाद के रनवे को सीमित उड़ानों के लिए खोल दिया गया।

दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम

मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, %पिछले दो दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया था, ताकि देख सकूं कि क्या किया जाना चाहिए? क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए? ऐसा ही गुजरात सरकार ने भी किया। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोगों भी ऐसा ही कर रहे थे।

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को तुरंत सक्रिय किया गया

उन्होंने आगे कहा, जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीमें जमीन पर काम कर रही थीं, जो भी संभव हो, बचाव करने की कोशिश कर रही थीं, आग पर काबू पाने और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थीं, ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली घटनाओं,

- ***विमान में क्रू और पैसेंजर (कुल 242)**
- ***241 मौतें (एक यात्री की जान बच गई।)**
- ***बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल 34 मौतें**
- ***(5 डॉक्टर+ 31 स्टाफ और वहां मौजूद अन्य लोग-275 की मौत)**

दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था, को तुरंत सक्रिय किया गया।

डीजीसीए ने भी 787 विमानों की विस्तृत निगरानी करने का आदेश दिया

राम मोहन नायडू ने कहा, हमारे देश में सुरक्षा के बहुत सख्त मानक हैं। जब यह घटना घटी, तो हमें भी लगा कि बोइंग 787 सीरीज की विस्तृत निगरानी की जरूरत है। डीजीसीए ने भी 787 विमानों की विस्तृत निगरानी करने का आदेश दिया है। आज हमारे भारतीय विमान बेड़े में 34 विमान हैं। मेरा मानना है कि 8 विमानों की पहले ही जांच हो चुकी है और तत्काल सभी विमानों की जांच की जाएगी।

प्रक्रिया या प्रोटोकॉल में कोई चूक न हो

उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों की कहानियां देखना बहुत ही दुखद हैं। हमने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह यात्रियों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करे। एक तरफ डीएनए परीक्षण भी हो रहा है, ताकि शवों की पहचान की जा सके और उन्हें संबंधित परिवारों को दिया जा सके। गुजरात सरकार इसके साथ समन्वय कर रही है। डीएनए परीक्षण की पुष्टि होने के बाद शवों को संबंधित परिवारों को दिया जाएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रक्रिया या प्रोटोकॉल में कोई चूक न हो।

ब्लैक बॉक्स के जरिए मिलेगी अहम जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AAIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच से एक महत्वपूर्ण अपडेट कल शाम 5 बजे के आसपास घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी है। AAIB टीम का मानना है कि ब्लैक बॉक्स की यह डिकोडिंग गहराई से जानकारी देने वाली है। दुर्घटना की प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना से पहले के क्षणों में वास्तव में क्या हुआ होगा? इसकी जानकारी भी ब्लैक बॉक्स के जरिए ही मिलेगी। हम इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि AAIB की ओर से पूरी जांच के बाद क्या परिणाम या रिपोर्ट सामने आएगी।

हर पहलू का विश्लेषण होगा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि जो भी थ्योरी इस वक्त चल रही है, जांच में उससे जुड़े हर पहलू का विश्लेषण होगा। तीन महीने में विस्तृत रिपोर्ट जारी होगी। रिपोर्ट में हादसे के अलावा भविष्य में ऐसी घटना न हो, इस पर सिफारिशें की जाएंगी।

अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र

लखनऊ।

नरेन्द्र मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी और सफल पुलिस भर्ती को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पुलिस में चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे। आरक्षी नागरिक पुलिस में 60,244 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। नव चयनित सिपाहियों में 12048 महिलाएं भी हैं। पहले परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद कर दी गई थी जिसे बाद में दोबारा कराया गया। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे होगा। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंच पर अपने हाथ से 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को समारोह स्थल पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। जिलों से अभ्यर्थियों को लाने के विशेष

- **लखनऊ में आज होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी**
- **आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनितों के चेहरे खिले**
- **नव चयनित सिपाहियों में 12048 महिलाएं**

प्रबंध हैं। अभ्यर्थियों को शनिवार रात लखनऊ के आसपास के जिलों में ठहराने का प्रबंध भी किया गया है। रविवार सुबह 10 बजे तक सभी अभ्यर्थी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां जिलेवार उनके बैठने का प्रबंध होगा। कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ समेत दस जिलों में डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। कानपुर नगर, रायबरेली, सुलतानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, महोबा, उन्नाव, अमेठी, बस्ती व जालौन में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई भी भारी वाहन लखनऊ की ओर नहीं आ सकेगा।

एआई-171 विमान हादसा: साइबर अटैक की आशंका, क्या विमान को 30 सेकंड में गिराया गया? उठे सवाल

मुंबई।

अहमदाबाद से लंदन (गैटविक) जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के क्रैश होने पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। फ्लाइट उड़ान भरने के महज 30 सेकंड में ही नीचे गिरकर क्रैश हो गई। ऐसे में शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने गंभीर सवाल उठाते हुए साइबर हमले की आशंका जताई है। इस भीषण विमान हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक और चिंता का माहौल है।

संजय राउत ने उठाए कई सवाल

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा, मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इस हादसे के पीछे कुछ गंभीर सवाल हैं। फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के भीतर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई? क्या यह महज तकनीकी खराबी थी, या फिर किसी दुश्मन देश द्वारा विमान की प्रणाली पर साइबर हमला किया गया था? उन्होंने हाल के दिनों में भारत के सैन्य और सामरिक प्रतिष्ठानों पर संभावित साइबर हमलों की घटनाओं का हवाला देते हुए इस हादसे की गहन तकनीकी और साइबर दृष्टिकोण से जांच की मांग की।

विमान रखरखाव और बोइंग

- **शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने गंभीर सवाल उठाते हुए साइबर हमले की आशंका जताई है। इस भीषण विमान हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक और चिंता का माहौल है।**

डील पर भी उठाए सवाल

संजय राउत ने विमानन क्षेत्र में रखरखाव की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अहमदाबाद में विमान का रखरखाव किस कंपनी या एजेंसी के अधीन था? उन्होंने यह भी कहा कि जब बोइंग के साथ विमान सौदा हुआ था, तब भाजपा इसके विरोध में थी, जबकि उस समय प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे। राउत ने कहा, आज लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं। विमानन क्षेत्र में रखरखाव सबसे अहम पहलू है। आखिर अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? वहां का रखरखाव मानक के अनुरूप है या नहीं? हादसे के बाद जिस तरह कुछ मंत्री घटनास्थल पर व्यवहार कर रहे थे, वह भी अत्यंत दुखद और असंवेदनशील था।

कुणाल कामरा के खिलाफ जल्द शुरू होगी विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही

मुंबई ।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाने वाले गीत को लेकर 'स्टैंड-अप कॉमेडियन' कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा विधायक प्रवीण दारेकर ने मार्च में बजट सत्र के दौरान राज्य विधान परिषद में कामरा और शिवसेना (उबाठा) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ नोटिस पेश किया था। विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले ने कहा, ''विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे ने भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति को नोटिस भेज दिया है।'' संपर्क करने पर लाड ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उनके नेतृत्व वाली समिति ने विशेषाधिकार हनन नोटिस पर चर्चा करने के लिए बैठक की और उन्होंने कामरा व अंधारे को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेताओं और मशहूर हस्तियों के बारे में अपनी बेबाक 'स्टैंड-अप कॉमेडी' के लिए मशहूर कामरा ने मार्च में शिवसेना प्रमुख शिंदे पर निशाना साधते हुए एक गीत गाया था, जिसके बाद कामरा के खिलाफ शिंदे समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा था।

नीट यूजी : लड़कों में महेश, तो लड़कियों में अविका ने किया टॉप

नई दिल्ली । इस साल राजस्थान के महेश कुमार ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर नीट यूजी 2025 के टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं, मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र के कृषांग जोशी को तीसरी रैंक मिली है। लड़कियों में अविका अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और देशभर में अव्वल रहीं। टॉपर्स की इस सूची में दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के कई छात्रों ने भी जगह बनाई है।

पूरे परिवार ने खाया जहर, तीन बच्चों की मौत, दंपति गंभीर

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक ही परिवार के पाँच सदस्यों ने जहर खा लिया। इस दर्दनाक घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई है और माता-पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रपुर ग्राम पंचायत के परलकोट विलेज-70 में हुई। गाँव के निवासी देवेंद्र बैरागी (36) ने कथित तौर पर खाने में जहर मिलाया और अपनी तीन मासूम बेटियों, दीप्ती बैरागी (12), जुतिका

बैरागी (9) और देवराज बैरागी (6) को खिला दिया। इसके बाद देवेंद्र बैरागी और उनकी पत्नी ने भी जहर का सेवन कर लिया। अधिकारियों ने दुखद जानकारी देते हुए बताया कि तीनों बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं देवेंद्र बैरागी और उनकी पत्नी को गंभीर हालत में पंखाजूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घर में ज़मीन पर बिछे एक बिस्तर पर तीनों बच्चों के शव पड़े हैं और उनके करीब थालियों में भोजन परोसा हुआ है। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की शुरुआती जाँच में सामने आया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी आर्थिक तंगी और परेशानियों के चलते परिवार ने इतना बड़ा और दुखद कदम उठाया होगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और घटना की विस्तृत जाँच की जा रही है। यह घटना पूरे क्षेत्र में शोक और सदमे का कारण बनी हुई है।

शानदार विरासत मलबे का ढेर बनी, कांग्रेस बोली- गाजा प्रस्ताव पर भारत की गैरमौजूदगी शर्मनाक

नई दिल्ली । कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्धविराम के लिए पेश प्रस्ताव पर मतदान से भारत की गैरमौजूदगी शर्मनाक है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि भारत ने हमेशा फलस्तीन का पक्ष लिया, लेकिन इस शानदार विरासत को मलबे में बदल दिया गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्धविराम प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। भारत हमेशा से शांति, न्याय और इंसानी अस्मिता का समर्थक रहा है। फलस्तीन में 60 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे

हैं। हजारों लोग भूख से मर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मदद भी रोक दी गई है। यह मानवीय त्रासदी है। भारत ने हमेशा फलस्तीन का समर्थन किया है और यह सिद्धांतों की बात है न कि रणनीति की, लेकिन आज शानदार विरासत को मलबे में बदल दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने पर भारत सरकार की आलोचना की। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि भारत सरकार ने तब स्टैंड लेने से इनकार कर दिया, जब गाजा में 60 हजार लोग मारे जा चुके हैं और गाजा की पूरी आबादी को बंद करके रखा गया है और उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये शर्मनाक है कि हमारी सरकार न सिर्फ गाजा के मुद्दे पर चुप है बल्कि इस्राइल सरकार के ईरान पर हमले की भी खुशी मना रही है, जबकि ईरान के पूरे नेतृत्व को मार दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया कि देश, संविधान के सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है। आज दुनिया में भेदभाव बढ़ रहा है, हमें मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए और सच्चाई और अहिंसा के साथ पूरी निडरता के साथ खड़े होना चाहिए।

नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विस्फोट, सीआरपीएफ जवान बलिदान

चाईबासा । ओडिशा-झारखंड सीमा पर शनिवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विस्फोट हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को ओडिशा-झारखंड सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान बलिदान हो गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सहायक उपनिरीक्षक सत्यवान कुमार सिंह

उस टीम का हिस्सा थे, जो 27 मई को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक पत्थर खदान के पास से माओवादियों की ओर से लूटे गए विस्फोटकों की तलाश में सारंडा जंगल में तलाशी ले रही थी। उन्होंने बताया कि ओडिशा पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम की ओर से तलाशी ली जा रही थी, तभी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में विस्फोट हो गया। पुलिस ने बताया कि सत्यवान कुमार सिंह सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन के थे। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बरहामपुर में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया।

आरोपी अधिकारी बरहामपुर में क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक के रूप में काम करता था।

मणिपुर में सुरक्षाबलों ने 300 से अधिक राइफल और गोला-बारूद बरामद किया

नई दिल्ली । मणिपुर में सुरक्षाबलों ने इंफाल घाटी के पांच जिलों से 300 से अधिक राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि खुफिया सूचना पर आधारित एक समन्वित अभियान के

दौरान मणिपुर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और सेना की संयुक्त टीमों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। अधिकारी ने कहा कि जब्त की गई वस्तुओं में 151 एसएलआर, 65 इंसास राइफल, 73 अन्य राइफल, पांच कार्बाइन, दो एमपी5 बंदूकें, 12 हल्की मशीन गन, एके सीरीज की छह राइफल, दो अमोघ राइफल, एक मोर्टार, छह पिस्तौल, एक एआर-15 और दो फ्लेयर बंदूक शामिल हैं।

दिल्ली में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा एलान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गंदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की दीवारों को गंदा करना या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि हर दिल्लीवासी को पर्यावरण प्रहरी बनना होगा ताकि शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। कहा कि सरकार अकेले शहर को व्यवस्थित नहीं कर सकतीं, इसके लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। लोगों से अपील की कि वे दिल्ली को साफ-सुथरा रखने में

अपना सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा, हम दिल्ली को लंदन या पेरिस नहीं, एक स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाना चाहते हैं। यमुना को साफ करने और दिल्ली को हरित बनाने की दिशा में भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने खजाना तो साफ किया लेकिन शहर की धूल नहीं हटाई। यह सब मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 'लैंडस्केपिंग के मूल सिद्धांत' पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन के दौरान कहा। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रॉबिन हिबू और पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव तलवार उपस्थित रहे।

इस्राइली रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी, कहा- अगर मिसाइलें दागनी बंद नहीं कीं तो जलेगा तेहरान

दुबई ।

इस्राइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने मिसाइलें दागनी बंद नहीं कीं तो तेहरान जल जाएगा। रक्षा मंत्री ने एक बैठक के दौरान यह बात कही। रक्षा मंत्री काट्ज ने शनिवार को इस्राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर, मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस्राइली नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काट्ज ने जोर देकर कहा, अगर अयातुल्ला अली खामेनेई इस्राइली घरेलू मोर्चे पर मिसाइलों से हमला करना जारी रखते हैं, तो तेहरान जल जाएगा। इजराइल काट्ज की यह टिप्पणी तब आई है,

जब शुक्रवार सुबह इस्राइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था। बाद में, ईरान ने शनिवार रात को इस्राइल पर जवाबी हमला किया और मिसाइलें दागीं। स्राइल ने अब तक अपने हमलों को ईरानी परमाणु और

सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित रखा है और उनसे जुड़े प्रमुख अधिकारियों को निशाना बनाया है। इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इस्राइल का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डा अगली सूचना तक बंद रहेगा। आईडीएफ ने कहा कि ईरान ने कल रात से लेकर अब तक कई बार इस्राइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि अधिकांश मिसाइलों को हवाई सुरक्षा ने रोक दिया है। सेना ने कहा कि छोटी संख्या की मिसाइलें हवाई सुरक्षा को भेदकर निकल गईं, जो हताहतों और क्षति का कारण बनीं। सेना ने बताया कि जिन जगहों पर मिसाइलें गिरीं, उनमें तेल अवीव, रमत गण और मध्य इस्राइल के रिशोन लेजियन के आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल हमलों में तीन इस्राइली लोग मारे गए और 70 अन्य घायल हो गए। आईडीएफ ने कहा कि उसके सभी बेस, जिसमें एयर बेस भी शामिल हैं, सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेना ने बताया कि शुक्रवार को दागे गए 100 ड्रोन के अलावा, रात भर इस्राइल पर दागे गए कई ड्रोन को इस्राइली वायु सेना और नौसेना ने मार गिराया।

एक नजर

इस्राइल ने युद्ध शुरू किया, हम उनको भागने नहीं देंगे, खामेनेई की नेतन्याहू को चेतावनी

तेहरान । ईरान और इस्राइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस्राइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस्राइल को चेतावनी दी है। खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई है। एक संदेश में ईरानी नेता ने कहा कि इस्राइल ने युद्ध शुरू किया। हम उन्हें उनके द्वारा किए गए इस महान अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस्राइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हम इस्राइली हमलों का बदला लेंगे। ईरानी सेना जवाबी हमले के लिए तैयार है। यह मत सोचिए कि उन्होंने हमला किया और सब खत्म हो गया, नहीं। उन्होंने काम शुरू किया और युद्ध शुरू किया। हम उन्हें उनके द्वारा किए गए इस महान अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। एक्स पर पोस्ट में खामेनेई ने कहा कि इस्राइली शासन ने बड़ी गलती की है, एक गंभीर त्रुटि की है, और लापरवाह काम किया है। इसका परिणाम यहूदियों के शासन को बर्बाद कर देगा। ईरानी राष्ट्र अपने लोगों के खून का बदला लिए बिना नहीं रहेगा, न ही वह अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को अनदेखा करेगा। हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं, और देश के अधिकारी और सभी लोग सशस्त्र बलों के पीछे हैं। खामेनेई ने कहा कि हम इस्राइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। हमें यहूदियों को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ताकत के साथ जवाब देंगे। यहूदियों के लिए अब जीवन कठिन हो जाएगा। हमारी सेनाएं दुश्मन को कड़ी टक्कर देंगी। ईरानी लोग हमारे साथ हैं। वे सशस्त्र बलों का समर्थन करते हैं, और ईरान के लोग निश्चिंत रहें और आश्वस्त रहें कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी सेनाएं यहूदियों को भारी नुकसान पहुंचाएंगीं। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग हमारे साथ हैं। वे सशस्त्र बलों का समर्थन करते हैं और ईश्वर की इच्छा से ईरान यहूदियों के शासन पर विजय प्राप्त करेगा।

ईरान के पास बातचीत का दूसरा मौका, वरना कुछ नहीं बचेगा, तेहरान को ट्रंप की धमकी

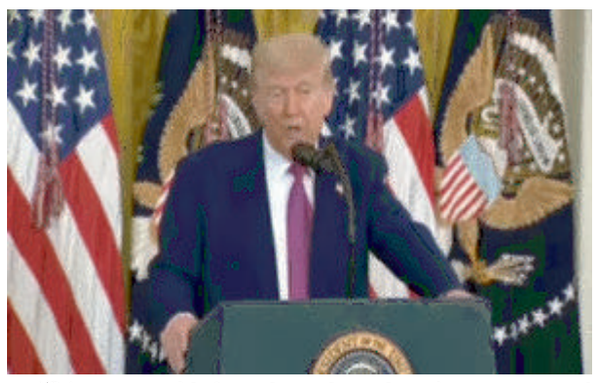

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइली हमलों के बीच ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु समझौते पर सहमत हो जाए और अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास यह दूसरा मौका है लड़ाई को और बढ़ने से रोकने का वरना कुछ नहीं बचेगा। वहीं इस्राइल ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात कही है। ईरान और इस्राइल के बीच जारी संघर्ष के बीच ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने कहा कि उनका ईरान पर हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इस्राइल ने उनके हथियारों का इस्तेमाल करके ही ईरान के परमाणु केंद्रों और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमला किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। इस्राइल के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं और उन्हें ये भी पता है कि इन हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है। इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष छिड़ने के बाद अमेरिका ने अपने युद्धक जहाजों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। ये बदलाव इस्राइल की मदद के लिए किया गया है। अमेरिका का डेस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडनर भूमध्यसागर की तरफ रवाना हो गया है। एक और डेस्ट्रॉयर भी पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस्राइल के हमले के बाद अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा करना अर्थहीन है। ईरानी विदेश मंत्रालय के इस बयान से रविवार को दोनों देशों के बीच ओमान में होने वाली बैठक खटाई में पड़ गई है। हालांकि मंत्रालय को बातचीत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि अमेरिका ने जो किया है, उसके बाद बातचीत करना बेकार है। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने हमला कर सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी हैं।

इस्राइली हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर फैला रेडिएशन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दावा

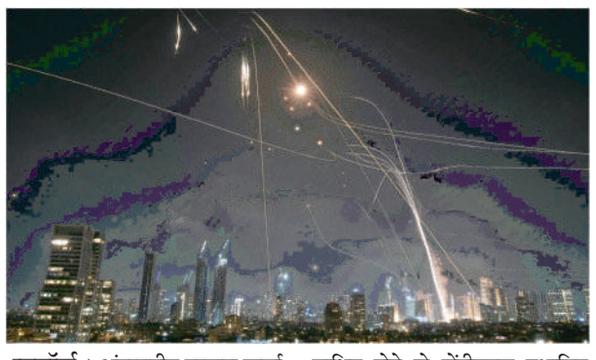

न्यूयॉर्क । अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी ने पुष्टि की है कि इस्राइली हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने पर रेडिएशन और केमिकल लीक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हालात की जानकारी देते हुए राफेल ग्रोसी ने यह जानकारी दी। ग्रोसी ने कहा कि इस्राइली हमले में नतांज परमाणु ठिकाने के ऊपरी और जमीनी ढांचा तबाह हो गया है।

हालांकि जमीन के भीतर मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नुकसान पहुंचने के कोई संकेत अभी नहीं मिले हैं। हालांकि विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हुए होंगे। नतांज साइट पर रेडियोएक्टिव और केमिकल प्रदूषण हुआ है। ग्रोसी ने बताया कि साइट के बाहर मौजूद रेडिएशन सामान्य स्तर का है और उससे पर्यावरण और लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रोसी ने कहा कि परमाणु केंद्र के भीतर जो रेडिएशन मौजूद है, वह अल्फा पार्टिकल्स हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रबंधों से मैनेज किया जा सकता है। एजेंसी ईरान के परमाणु रेगुलेटरी अथॉरिटी के लगातार संपर्क में है और नुकसान की समीक्षा कर सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ग्रोसी के अनुसार, ईरान ने उनके परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों की जानकारी दी, जिनमें फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और एसफहान कॉम्पलेक्स शामिल हैं। इन केंद्रों का इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन के लिए किया जा रहा है। एजेंसी के प्रमुख ने परमाणु केंद्रों पर हमले पर चिंता जाहिर की और कहा कि परमाणु केंद्रों पर कभी भी हमले नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इस तरह के हमले परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से 241 किलोमीटर दूर स्थित नतांज परमाणु केंद्र ईरान का यूरेनियम संवर्धन के लिए सबसे अहम केंद्र है। ईरान फिलहाल 60 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन इसी केंद्र पर कर रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ही 200 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के परमाणु केंद्रों को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही ईरान की सेना के कई शीर्ष कमांडर और दो परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं।

बाली में पर्यटक विला में फायरिंग, एक आस्ट्रेलियाई युवक की मौत; दूसरा घायल

बाली । इंडोनेशिया के पर्यटक द्वीप में एक विला में फायरिंग हुई है। इसमें एक आस्ट्रेलियाई युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हमले में एक अन्य आस्ट्रेलियाई व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय पुलिस प्रमुख आरिफ बटुबारा ने कहा कि जांच चल रही है और पुलिस संभावित गवाहों की तलाश कर रही है। बटुबारा ने बताया कि दोनों पीड़ितों को बाली की प्रांतीय राजधानी डेनपसार के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को अभी तक गोलीबारी के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है।

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता और माता-पिता का गर्भपात कराने से इनकार, हाईकोर्ट ने बंद किया मामला

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात में देरी को लेकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पीड़िता और उसके माता-पिता ने गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया था। सरकारी वकील मोहन सौसरकर ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को गर्भपात से जुड़ी संभावित समस्याओं के बारे में समझाया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी गर्भपात के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि वे लड़की की भलाई के लिए गर्भावस्था को जारी रखना चाहते हैं। न्यायमूर्ति अमित सेठ ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया, चूंकि पीड़िता और उसके माता-पिता गर्भपात नहीं करवाना चाहते और गर्भावस्था को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। अब इस याचिका में किसी और आदेश की जरूरत नहीं है। 5 जून को हाईकोर्ट ने बालाघाट जिले की दुष्कर्म पीड़िता के मामले का स्वत संज्ञान लिया था, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता सात महीने से ज्यादा गर्भवती थी और गर्भपात में देरी हो रही थी। अदालत ने राज्य सरकार से मामले की विस्तृत जानकारी मांगी थी। यह मामला तब हाईकोर्ट तक पहुंचा जब बालाघाट जिले के जिला न्यायाधीश ने 26 मई को एक पत्र भेजा और साथ में स्थानीय अस्पताल के सिविल सर्जन की रिपोर्ट भी भेजी। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी. खोत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध की रिपोर्ट पुलिस को कब दी गई थी। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या 20 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सही तरीके से किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी और केस की डायरी के साथ यह बताने को कहा कि आखिर किस वजह से लड़की के गर्भपात में इतनी देरी हुई।

कार्लो के रूप में ईसाइयों को मिलेगा पहला मिलेनियल संत; पोप देंगे उपाधि, गॉड इंफ्लूएंसर के तौर पर पहचान

रोम ।

इतावली मूल के कार्लो एक्यूटिस को पोप लियो सात सितंबर को संत की उपाधि प्रदान करेंगे। वह संत बनने वाले पहले मिलेनियल होंगे। 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। शुक्रवार को पोप लियो 14वें ने घोषणा की कि कार्लो एक्यूटिस को 7 सितंबर को संत घोषित किया जाएगा। बता दें कि कार्लो एक्यूटिस को गॉड इंफ्लूएंसर कहा जाता है। वह संत की उपाधि पाने वाले पहले मिलेनियल (1981-1996 के बीच जन्में) होंगे। 3 मई 2006 को लंदन में जन्में कार्लो की 15 साल की उम्र में ल्यूकीमिया से मौत हो गई थी। मृत्यु के दो दशक बाद उन्हें संत की उपाधि दी जाएगी। रोमन कैथोलिक चर्च में किसी भी उम्र के शख्स को संत की उपाधि दी जाती है, हालांकि ये दर्जा उनके निधन के बाद ही दिया जाता है। कार्लो बचपन से ही दूसरे बच्चों से अधिक धार्मिक थे। उन्होंने काफी कम उम्र में ही कोडिंग सीख ली थी और एक वेबसाइट बनाकर कैथोलिक सोसायटी में हो रहे चमत्कारों को एकसाथ लिस्ट किया था और चर्च की शिक्षाओं को फैलाया था। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्लो ने चमत्कारिक ढंग से 2 लोगों की जानें बचाई थीं। पहला मामला कोस्टा रिका की लिलियाना नाम की एक महिला से जुड़ा है। उनकी बेटी को साइकिल से गिरकर गंभीर चोट लग गई थी। इसको लेकर जब उन्होंने 8 जुलाई साल 2022 में कार्लो की कब्र पर प्रार्थना की तो वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। वहीं साल 2023 में अग्नाशय रोग से पीड़ित एक लड़के ने कार्लो के कपड़े छुए थे, जिसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया था।

इस्राइली हमलों में ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद नई तैनाती, जनरल हातमी बने सेना के मुख्य कमांडर

तेहरान ।

इस्राइली हमलों में अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरान ने नए अफसरों की तैनाती कर दी है। ईरान के कमांडर इन चीफ अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान की सुरक्षा और इस्राइल को जवाब देने के लिए अपने भरोसेमंद अफसरों के हाथ में सैन्य नेतृत्व सौंपा है।

खामेनेई ने मेजर जनरल अमीर हातमी को ईरानी सेना का मुख्य कमांडर बनाया है। जबकि मेजर जनरल सैय्यद अब्दुलरहीम मौसवी को सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। मेजर जनरल अमीर हातमी 2013 से 2021 तक ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अपने आदेश में अयातुल्ला अली खामेनेई ने हातमी के समर्पण, क्षमता और अनुभव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में सेना में परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इसके अलावा खामेनेई ने इस्राइली हमले में

पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज (ष्ट्रस्त्र) जनरल मोहम्मद होसैन बाघेरी की मौत के बाद मेजर जनरल सैय्यद अब्दुलरहीम मौसवी को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। आदेश में खामेनेई ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद होसैन बाघेरी की मौत के बाद मेजर जनरल सैय्यद अब्दुलरहीम मौसवी की सराहनीय सेवा और अनुभव के मद्देनजर उनको सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस्राइली हमलों में लेफ्टिनेंट जनरल होसैन सलामी की मौत के बाद मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को IRGC का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया। खामेनेई ने कहा कि मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की सराहनीय सेवाओं और बहुमूल्य अनुभव को देखते हुए उन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया जाता है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने लेफ्टिनेंट जनरल घोलामाली रशीद की मौत के बाद मेजर जनरल अली शादमानी को खतम अल-अनबिया (पीबीयूएच) सेंट्रल मुख्यालय का कमांडर नियुक्त किया गया है। इस्राइल के हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसरों की मौत हुई है। इसमें आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल होसैन सलामी, ईरान के सशस्त्र बलों के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी शामिल थे। इसके अलावा आईआरजीसी की वायु सेना के प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह की भी मौत हो गई। इस्राइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करने के करीब है। ईरानी शासन के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार इस्राइल और दुनिया के लिए खतरा हैं। जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले करके जवाबी कार्रवाई की।

हर बार डेड बॉडी मिल जाए ये जरूरी नहीं, पंजाब के एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिली धमकी

नई दिल्ली । बठिंडा में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल सिंह मेहरो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसके दो साथियों को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मेहरो ने अब पंजाब के सोशल मीडिया influencers को धमकी दी है कि वे अभद्र कंटेंट सोशल मीडिया पर न डालें. खास तौर पर अमृतसर की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर दीपिका लूथरा को उसने धमकी दी है कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अभद्र कंटेंट न डालें. हालांकि लूथरा ने अपने सोशल मीडिया से कथित अभद्र कंटेंट हटा लिया है और ऐसा कंटेंट डालने के लिए माफी भी मांगी है. मेहरो ने धमकी में कहा है कि पार्किंग की जगहें सिर्फ बठिंडा में ही नहीं हैं और जगह भी हैं और हर बार डेड बॉडी मिल जाए ये जरूरी नहीं. मेहरो ने ही कंचन कुमारी को एक प्रमोशन के बहाने बठिंडा बुलाया था और इसके दो निहंग सिंह साथियों जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह ने कंचन कुमारी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. बठिंडा के भुच्चो में आदेश अस्पताल के नजदीक एक पार्किंग में कार में कंचन कुमारी का शव बुधवार रात को मिला था. अमृतपाल सिंह मेहरो ने कंचन कुमारी को उसके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के लिए धमकियां भी दी थीं. अमृतपाल सिंह मेहरो ने 2022 का विधानसभा चुनाव पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी के तौर लड़ा था. वो कौम दे राखे नाम से एक संगठन भी चलाता है और अपने आप को सिख मर्यादाओं के रक्षक के रूप में बताता है.

ट्रंप के खिलाफ आज नो किंग कार्यक्रम; लॉस एंजिलिस में मरीन तैनात, देशभर में प्रदर्शन की तैयारी तेज

लॉस एंजिलिस । अमेरिका में आव्रजन (इमिग्रेशन) छापों को लेकर एक हफ्ते से चल रहे विरोध के बीच करीब 200 अमेरिकी मरीन सैनिकों को लॉस एंजिलिस में एक फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात किया गया। कारण है कि शनिवार को अमेरिका भर में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स (कोई राजा नहीं) नाम से एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इसी दिन वॉशिंगटन डीसी में एक सैन्य परेड भी होगी, जिसमें सैनिक मार्च करेंगे और टैंक सड़कों पर दिखाई देंगे। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने वाशिंगटन, डीसी में ट्रंप की योजनाबद्ध सैन्य परेड के साथ मेल खाने के लिए पूरे देश में नो किंग्स कार्यक्रमों की योजना बनाई हैं। शनिवार के प्रदर्शनों से देशभर में तनाव भड़कने की आशंका को देखते हुए नेशनल गार्ड को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं।

फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए तैनात मरीन जवानों को नेशनल गार्ड के कुछ जवानों की जगह तैनात किया गया है, ताकि नेशनल गार्ड अब छापों के दौरान पुलिस की सुरक्षा कर सकें। मरीन पूरी तरह से हथियारों, संचार उपकरणों और

सुरक्षा गियर के साथ आए हैं, और शुक्रवार से तैनाती शुरू कर दी गई है। बता दें कि मरीन की तैनाती उस फैसले के बाद हुई है, जिसमें 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक फेडरल जज के आदेश को रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि ट्रंप को कैलिफोर्निया को नेशनल गार्ड की कमान लौटानी चाहिए क्योंकि गार्ड की तैनाती गैरकानूनी थी और ट्रंप के अधिकारों से बाहर थी। जज ने मरीन की तैनाती पर कोई फैसला नहीं दिया है। इन दिनों कैलिफोर्नियां और ट्रंप प्रशासन के बीच तकरार भी तेज होता हुआ दिख रहा है। जहां बीते दिनों कैलिफोर्नियां के गवर्नर गैविन न्यूसम ने सैनिकों की तैनाती को राज्य की संप्रभुता पर हमला बताया है और कोर्ट का रुख किया है। ट्रंप ने संविधान की उस धारा का हवाला दिया है, जो विद्रोह या विद्रोह की आशंका होने पर सैन्य बल लगाने की इजाजत देती है।

हालांकि, एक फेडरल जज ने कहा कि लॉस एंजिलिस की स्थिति विद्रोह जैसी नहीं है और आदेश दिया कि नेशनल गार्ड का नियंत्रण कैलिफोर्निया को वापस मिले। लेकिन नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका स्वागत किया और कहा, अगर मैंने सेना नहीं भेजी होती, तो लॉस एंजिलिस जल रहा होता।

पाकिस्तान नहीं होता न्यूक्लियर पावर? हिमंत बिस्वा सरमा बोले- 1980 के दशक में भारतीय सेना की होती एयरस्ट्राइक

असम। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी देता रहता है. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पाकिस्तान के परमाणु शक्ति बनने का कारण कांग्रेस सरकार को बताते हुए इसे ऐतिहासिक चूक घोषित कर दिया. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक चूक के कारण भारत ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने दिया. उन्होंने कहा, आज जब दुनिया परमाणु खतरों को समय रहते खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है, 1980 के दशक में भारत की निष्क्रियता एक दर्दनाक सबक बन चुकी है, जिसमें क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने छूटी हुई ऐतिहासिक घड़ियों के बार में कहा, रॉ को पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान का 'काहूटा प्लांट' यूरेनियम संवर्धन का गढ़ बन चुका है. भारतीय सेना ने कांग्रेस की केंद्र सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया था कि काहूटा पर प्रीएम्टिव स्ट्राइक (एयरस्ट्राइक) की जाए. उन्होंने कहा, खुफिया जानकारी से लेकर संयुक्त हवाई हमले की योजना तक इजराइल ने मदद की पेशकश की थी. जामनगर एयरबेस को लॉन्चपैड के रूप में चिन्हित भी किया गया था. भारत के पास इस खतरे को समय रहते खत्म करने के लिए सामर्थ्य और राजनीतिक सहमति दोनों थी. लेकिन अंतिम समय में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के डर से इंदिरा गांधी पीछे हट गईं. वहीं, राजीव गांधी ने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वैश्विक दबाव के आगे कूटनीति को प्राथमिकता दी. जिसके नतीजे आज भी गूंजते हैं. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले न करने का समझौता किया. इसके बाद 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण

कर दुनिया को चौंका दिया. जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत को महंगे परमाणु हथियारों की दौड़ में उतरना पड़ा. उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध, आतंकवाद और सीमापार हमले सब पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा कवच के साए में हुए. वहीं, आज भी पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नैतिक वैधता पाने का खेल खेलता है. उन्होंने आगे कहा, हैरानी की बात तो यह है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई (एम) ने अपने घोषणापत्र में भारत की परमाणु नीति को खत्म करने की बात कही! उन्होंने कहा, जहां मजबूत नेतृत्व दूरदर्शिता और साहस की मांग करता है, कांग्रेस ने संकोच और देरी दिखाई. एक ऐतिहासिक अवसर, जिससे भारत की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी, उसे कुछ दिनों की अंतरराष्ट्रीय सहमति के लिए कुर्बान कर दिया गया. और इसकी रणनीतिक कीमत भारत और पूरा क्षेत्र आज तक चुका रहा है.